भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2928
13.08.2026 को उत्तर के लिए

वैश्विक जलवायु कार्रवाई में प्राप्त उपलब्धि

2928. श्री सुजीत कुमार :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को तय समय-सीमा से पहले पूरा करने में प्राप्त की गई प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) इस उपलब्धि में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं;
(ग) भारत की अगली पीढ़ी के लिए अधिक महत्वाकांक्षी एनडीसी लक्ष्यों हेतु रूपरेखा क्या है; और
(घ) वैश्विक जलवायु कार्रवाई में भारत की इस उपलब्धि को मिली अंतरराष्ट्रीय मान्यता और उसका महत्व क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) नामतः तीन मात्रात्मक लक्ष्यों से बना है, जिसमें पहला हमारे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की प्रति इकाई आर्थिक उत्पादन पर होने वाले उत्सर्जन में कमी लाना, स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों की हिस्सेदारी बढ़ाना और अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण शामिल हैं।

भारत ने वर्ष 2022 में वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में अपने सकल घरेलू उत्पाद (एनडीसी) की प्रति इकाई आर्थिक उत्पादन पर होने वाले उत्सर्जन में 37.38% की कमी प्राप्त की, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रति इकाई आर्थिक उत्पादन पर होने वाले उत्सर्जन में 45% की कमी करना है। जून वर्ष 2025 में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से संचयी स्थापित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 50% से अधिक हो गई। इस प्रकार, भारत ने निर्धारित समयसीमा से पाँच वर्ष पहले ही अपने एनडीसी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। दिनांक 30 जून 2026 तक, देश की

कुल स्थापित विद्युत शक्ति क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी 54.18% थी। भारत ने वर्ष 2005 से 2022 के दौरान 2.44 बिलियन टन सीओ2 के समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया है, जबकि एनडीसी लक्ष्य वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5-3.0 बिलियन टन सीओ2 के समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का है।

अप्रैल, 2026 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को प्रस्तुत भारत की पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट में बताया गया है कि आर्थिक विकास और जीडीपी से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को अलग करने का श्रेय नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन को बढ़ावा देने वाली नीतियों, सभी आर्थिक कार्यकलापों की ऊर्जा दक्षता में सुधार को दिया जा सकता है। गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत ऊर्जा क्षमता के हिस्से पर एनडीसी लक्ष्य की प्रारंभिक उपलब्धि कई नीतियों द्वारा संभव हुई है जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और उसे राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड में एकीकरण को बढ़ावा देती हैं। राष्ट्रीय और राज्य सरकारों द्वारा संरक्षण और पुनर्स्थापना को उच्च प्राथमिकता दिए जाने के कारण कार्बन सिंक का निर्माण संभव हो सका है। यह दृष्टिकोण वनों और जैव विविधता के संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाने और वन आश्रित समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा करते हुए संरक्षण कार्यकलापों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नीतियों, अधिनियमों, नियमों, कार्यक्रमों और योजनाओं के ढांचे में परिलक्षित होता है।

वर्ष 2035 के लिए एनडीसी लक्ष्यों को और अधिक महत्वाकांक्षी बनाया गया है, इसके तहत वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई आर्थिक उत्पादन पर होने वाले उत्सर्जन में 47% की कमी लाने, गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से संचयी स्थापित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 60% तक पहुँचाने तथा वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से 3.5 से 4.0 बिलियन टन सीओ2 समतुल्य का कार्बन सिंक बनाने का मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एनडीसी में संधारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देने, अनुकूलन क्षमता बढ़ाने और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य के अनुरूप जलवायु अनुकूल स्वच्छ तौर तरीके अपनाने के उद्देश्य से पांच गुणवत्ता-परक लक्ष्य भी शामिल हैं।

भारत की महत्वपूर्ण जलवायु प्रतिबद्धताओं को लागू करने में प्रगति को कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय निकायों से व्यापक मान्यता मिली है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए), खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए), आदि शामिल हैं।

****